

Amendment in Contract Labour (Abolition and Regulation) Act

*262. SHRI J. CHITHARANJAN:†

SHRI GAYA SINGH:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the decision and observation made by the Hon'ble Supreme Court of India with regard to contract workers in the judgement relating to Gujarat State Electricity Board and Air Corporation Ltd. will be incorporated in the contract Labour (Abolition and Regulation) Act;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if so, what other amendments are proposed to be effected in the said Act?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA):

(a) to (c) In the wake of the two landmark judgements of the Supreme Court in the cases of Gujarat State Electricity Board and Air India Statutory Corporation Ltd. Vs. United Labour Union, representations have been received both from the employers' as well as from the employees' organisations. The changes or amendments to be made in the existing law, if any, after taking into consideration all relevant factors, have not yet been finalised.

SHRI J. CHITHARANJAN: Hon. Chairman, Sir, I regret to state that the reply given by the hon. Minister is an evasive one and not a straight one. Sir, the point is that the Supreme Court has given a certain landmark judgement on the basis of which certain issues faced by the contract labour have been set at rest. The question is whether the Government will amend the Contract Labour (Abolition and Regulation) Act in the light of the judgement given by the Supreme Court. This is the real question that has not been replied to. Sir, I would like to get a clear answer in this regard.

डॉ. सत्यनारायण जटिया: जैसा कि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं जिन दो प्रकारों के बारे में, इसमें गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड बनाम

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri J. Chitharanjan.

हिन्द मजदूर सभा है, उसका जो फैसला आया था उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उसमें यह था कि सभी फर्मों को स्वयं ठेका श्रम समाप्त करने के लिए स्वतः पहल करनी चाहिए।

दूसरा जो उसका निर्देश था उसमें यह था कि इन सारी बातों को सुनिश्चित करने के लिए ठेका श्रमिक कानून को नियमित किया जाना चाहिए। सरकार इस बात की जांच करने के लिए जांच समिति बनाए और जांच समिति बनाकर समूची सरकार इस बात को लागू करने का प्रयास करे कि वहां पर ठेका श्रमिक को रेग्युलेट किया गया है।

तीसरी बात यह थी कि जो कांटेक्टर थे, जहां से मजदूर बेरोजगार हो जाता है, निकाला जाता है, ऐसे रोजगार के प्रश्न को औद्योगिक न्याय निर्णय की प्रक्रिया में शामिल किया जाए और उस दृष्टि से उसमें संशोधन करने का काम करे। यह तो गुजरात इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम हिन्द मजदूर सभा के फैसले में था। दूसरे एयर इंडिया के बारे में पूछा गया था उसमें इस बात को और संक्षिप्त रूप करके समुचित सरकार के बारे में कहा गया है और जो सार्वजनिक उपक्रम है उन सब में केन्द्रीय सरकार प्रमुख नियोक्ता हो, इस प्रकार की बात कही गई है। इसी के साथ-साथ केन्द्रीय औद्योगिक संबंधी तंत्र के माध्यम से श्रम मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार केवल अधिसूचना का प्रवर्तन करती है। इस बारे में कार्यवाही करने की दृष्टि से जो उपाय किए जाने चाहिए, इस प्रकार का भी उसमें प्रबन्ध किया गया है और सरकारी उपक्रम के बारे में बात कही गई है और उसमें यह भी कहा गया है कि ठेका श्रम का अर्थ क्या है। ऐसी धारा-10(2) के अन्तर्गत बात कही गई है, उसको शामिल किया है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो धारा-10(2) के बारे में भी मैं उनका उल्लेख कर सकता हूं।

SHRI J. CHITHARANJAN: Unfortunately, the Minister is again evading the question. The question is, the Supreme Court had taken certain decisions about certain disputed issues regarding contract labour. It has already become a case law. My question is whether the Government will amend the Contract Labour (Abolition and Regulation) Act, in line with the decision taken by the Supreme Court?

डा. सत्य नारायण जटिया: बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मैंने कहा है कि इसके निषेध में जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है उसमें कानून में अपेक्षित संशोधन करने की बात सरकार के विचाराधीन है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि संशोधन लागू करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए।

श्री गया सिंह: सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह स्पष्ट नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है क्या सरकार उस निर्णय के आलोक में संशोधन का विचार कर रही है? पुरे देश से ठेकेदार

मजदूरों के केसेस आए हैं परंतु वे लेबर डिपार्टमेंट में पेंडिंग पड़े हैं, चाहे वह माइंस क्षेत्र का हो, संगठित क्षेत्र का हो या असंगठित क्षेत्र का हो और अभी यह चर्चा भी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत कोई और संशोधन आने वाला है, कृपया मंत्री जी इसे स्पष्ट करें और यह बताएं कि वह संशोधन कब तक आएगा?

डा. सत्य नारायण जटिया: जहां तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत संशोधन करने की बात है, आपने कहा कि सारे ठेका श्रमिकों को प्रतिषेध करना चाहिए, रोकना चाहिए। कानून की धारा 10(i) में बताया गया है कि ठेका श्रमिक वहां नहीं लगाए जाने चाहिए जहां पैरलल नेचर ऑफ वर्क हो, मूल उत्पादन प्रक्रिया के काम हों। इसलिए स्पष्ट है कि प्रमुख नियोक्ता इस बात को देखें कि ऐसी जगह पर जहां पैरलल नेचर ऑफ वर्क, नियमित, दैनन्दिन प्रकार के काम हों उन कामों में ठेका श्रमिक नहीं लगाएं, धारा 10 इस बात को व्यक्त करती है। इन सारी बातों पर निगरानी रखने के लिए सेंट्रल एडवाइजरी कांट्रैक्ट बोर्ड बना हुआ है। इसमें मजदूरों, नियोक्ता के खास प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी शामिल हैं, एक चेयरमैन शामिल हैं। इन 19 लोगों की कमेटी के माध्यम से सरकारी जांच का काम किया जा सकता है।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, through you, I would like to put one question to the Labour Minister. The hon. Labour Minister is aware that we are putting questions and he is making statements, but the reality is altogether different. It is not only in the case of Gujarat State Electricity Board and Air Corporation Limited, the problem is rampant in the country and in most of the industries, particularly in Gujarat, Maharashtra and in his own State, Madhya Pradesh. Contract labour is being used indiscriminately even in places where permanent workers are there, or in certain cases where permanent workers are not in a position to perform their job because of the hazardous nature of the job and they ask for hazard allowance. There, contract labourers are being used and the condition of these contract labourers is quite deplorable. I would like to know from the hon. Labour Minister whether he is also aware that it is not only contract Labourers, but even bonded labourers are being used, particularly, in Uttar Pradesh. There are some reports in the newspapers in this regard. So, would the Labour Minister be kind enough to clarify whether the objective reality is something else and he is stating something else. It is not only statute or acts; it involves the health of the poor workers. It should be an all-out effort of all of us, and the Government, in particular, the Department, in particular. How

[10 August, 2000]

RAJYA SABHA

is he going to resolve this problem? Would the hon. Minister kindly reply?

डा. सत्य नारायण जटिया : माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है उसमें यह कहा गया है कि क्या सरकार के पास इस प्रकार की जानकारी है इन सारी बातों को निर्मूल करने के लिए कि कांटेक्ट लेबर नहीं लगाई जानी चाहिए। जहां तक माननीय सदस्य जानते हैं ठेका लेबर लगाने के लिए केवल उन्हीं कामों पर प्रतिषेध लगाया गया है जो मुख्य काम हैं, उत्पादन से संबंधित हैं। जहां तक इस बात में कोई शिकायत प्राप्त होने की बात है उस संबंध में मेरा कहना है अभी तक इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिससे कि इस संबंध में कोई फैसला करने का काम आगे बढ़ाया जा सके। कोई शिकायत प्राप्त होने पर ही हम जरूरी कार्रवाई करेंगे।

Review of foreign policy in relation to Pakistan

*263. SHRI GHULAM NABI AZAD: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are considering any proposal to review the foreign policy pertaining to Pakistan's involvement in cross-border terrorism; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) No, Sir.

(b) Government remains steadfast in its resolve to defeat Pakistan's state sponsorship of terrorism in Jammu and Kashmir and/ or elsewhere in India.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, the established policy of the Government of India, all along, with regard to the issue of Kashmir and solving the problem of Kashmir has been that it shall be discussed and solved bilaterally with no third-party intervention whatsoever. The Government of India has taken a position that India shall not talk to Pakistan till Pakistan stops cross-border terrorism. Sir, Pakistan is continuously aiding, abetting, training and sponsoring terrorism for the last one decade. As a result of which, thousands of people have been killed and lakhs and lakhs of people have suffered in the State of Jammu and Kashmir. Part (a) of my supplementary is: Should Pakistan decide not to stop cross-border terrorism for